दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 24 जुलाई 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक-292

महत्वपूर्ण एवं खास

सुमाड़ी गांव में स्थापित होगा एन.आई.टीः निशंक

» सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगा शिलान्यास

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर के संबंध में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत एवं पौड़ी-गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ बैठक की। बैठक के बाद निशंक ने स्पष्ट किया कि सुमाड़ी गांव (श्रीनगर, गढ़वाल) में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 309 एकड़ में से 203 एकड़ को परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थान पर स्थाई परिसर का निर्माण किया जाएगा । निशंक ने बताया कि बैठक में सहमति बनी है कि आगामी सत्र श्रीनगर के अस्थाई परिसर में ही प्रारंभ किया जाएगा और एनआईटी जयपुर से बच्चों को लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगले सत्र से प्रवेश की पूरी प्रक्रिया श्रीनगर में होगी ।

पुलवामा-कश्मीर में एनआईए कर रही छापेमारी

श्रीनगर (आरएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार व्यापार करने वाले दो व्यापारियों के परिसरों पर छापेमारी की। यह छापेमारी पुलवामा और श्रीनगर जिलों में की गई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के सहयोग से एनआईए अधिकारियों ने पुलवामा जिला के केलर क्षेत्र में गुलाम अहमद वानी के घर पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि प्रशासन द्वारा एलओसी पार व्यापार को 14 फरवरी 2019 को रद्द करने से पहले वानी इसमें शामिल था। एनआईए के सूत्रों ने कहा, एक अन्य छापेमारी श्रीनगर में परिमपोरा फल मंडी में की गई। ये छापेमारियां एनआईए द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण (टैरर फंडिंग) की जांच के अंतर्गत की गई हैं। एनआईए अब तक कश्मीर के प्रसिद्ध उद्योगपति जहूर वटाली और कई अन्य अलगाववादी नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

दिल्ली लाए गए कर्नाटक के बागी विधायक

» सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नईदिल्ली(आरएनएस)। कर्नाटक के बागी विधायक अब दिल्ली लाए गए हैं. इन्हें दिल्ली में ही किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है. इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को मुंबई के पांच सितारा होटल में रखा गया था. ज्ञात हो कि कर्नाटक का सियासी नाटक पिछले 21 दिन से जारी है. हर बार नई डेडलाइन दी जाती है, लेकिन एचडी कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाता. सोमवार को भी देर रात जनता दल सेक्यूलर-कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी विधायकों का टकराव होता रहा. बीजेपी विधायक विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर अड़े रहे. इसके बाद स्पीकर केआर रमेश कुमार ने सदन को सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. स्पीकर ने कुमारस्वामी सरकार को हर हाल में मंगलवार शाम 6 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है. फ्लोर टेस्ट होने तक सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हो पाएगी.

दक्षिण कोरिया ने रूसी लड़ाकू विमानों को चेतावनी देते हुए गोलियां चलायीं

सियोल। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसने देश की हवाई सीमा में घुस आए रूसी लड़ाकू विमानों को चेतावनी देते हुए उनपर गोलियां चलायीं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस के कई लड़ाकू विमान मंगलवार को देश के पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर गए। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी और चेतावनी के लिए रूसी विमानों पर गोलियां चलायीं। उसका कहना है कि मंगलवार को ही चीन के लड़ाकू विमानों ने भी देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया।

पहले महिला और फिर पुरुष को उतारेगा चांद पर

» नए मून मिशन पर नासा

वाशिंगटन। दुनिया इस साल मानव के चांद पर कदम रखने की 50वीं वर्षगांठ मना रही है, इसी आलोक में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह एक अन्य कार्यक्रम के तहत इस दिशा में एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल करने को तैयार है। कार्यक्रम के तहत पहले महिला और उसके बाद पुरुष को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इस कार्यक्रम को आर्टेमिस नाम दिया गया है, जो अपोलो की जुड़वा बहनें मानी जाती हैं। यह चंद्रमा और आखेट (शिकार) की देवी का नाम भी है।

एजेंसी की मानें तो उसका स्पेस कार्यक्रम आर्टेमिस, उसके मंगल मिशन में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। नासा ने एक बयान में कहा, मंगल पर हमारा रास्ता आर्टेमिस बनाएगा। नया आर्टेमिस मिशन अपोलो कार्यक्रम से साहसिक प्रेरणा लेकर अपना रास्ता तय करेगा। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगाएंगे, जहां पहले कोई भी नहीं गया है। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हुए उस तकनीक का भी परीक्षण करेंगे जो सौरमंडल में मनुष्य की सीमाओं को विस्तार देगी।

एजेंसी ने कहा, चांद की सतह पर हम पानी, बर्फ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाएंगे, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष की और आगे तक की यात्रा संभव हो सके। चंद्रमा के बाद मनुष्य की अगली बड़ी उपलब्धि मंगल ग्रह होगी। चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी साल 2024 में होगी। इस कार्यक्रम पर लगभग 30 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इसी के साथ स्पेसफ्लाइट अपोलो-11 की कीमत भी करीब इतनी ही होगी।

अमेरिका द्वारा 1961 में शुरू कर 1972 में समाप्त किए गए अपोलो कार्यक्रम की लागत 25 अरब डॉलर थी। अपोलो-11 मिशन के तहत 50 साल पहले दो अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे थे। इस मिशन पर उस समय लागत छह अरब डॉलर आई थी, जो इस समय 30 अरब डॉलर के बराबर है।

नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन के अनुसार, अपोलो कार्यक्रम और आर्टेमिस के बीच मुख्य अंतर यह है कि पहले जहां चांद की सतह पर महज मौजूदगी दर्ज कराई गई थी, वहीं अब वहां एक स्थायी मानव उपस्थिति होगी। इस कार्यक्रम में 2020 में चंद्रमा के आसपास एक मानवरहित मिशन काम करेगा। जबकि इसके दो साल बाद एक मानवयुक्त मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा की जाएगी।

अगले चंद्र मिशनों को स्पेस लांच सिस्टम द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। रॉकेट को नासा और बोइंग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो पूरा बनने के बाद सबसे बड़ा रॉकेट होगा। नासा की योजनाओं के अनुसार, साल 2022 और 2024 के बीच के पांच मिशनों को निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाएगा।

दो सौ करोड़ की हेराइन ले जाते दो अफगानी गिरफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 किलोग्राम हेरोइन के साथ दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. स्पेशल सेल ने हरियाणा स्थित सोनीपत के कुंडली में मरियापुरी रोड पर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा था. जहां किशमिश के 102 डिब्बे बरामद किए गए. जिनमें 204 पॉलीपैक कार्डबोर्ड लेयरिंग के बीच छुपाए गए थे.

इन पॉलीपैक में ही करीब 50 किलोग्राम हेरोइन छुपाकर ले जाई जा रही थी. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक कंधार का है और दूसरा हेलमंद का है. हेरोइन की यह खेप वाघा-अटारी बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुई थी. इसे देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाना था.

बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की थी. इसकी लक्जरी गाड़ियों से देशभर में सप्लाई की जानी थी. इस दौरान पुलिस ने पांच लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

ट्रम्प के दावे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा

» प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की

नईदिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर मंगलवार को लोकसभा में मोदी से जवाब देने की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता करने का आग्रह किया था।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर ट्रंप का दावा सही है तो पीएम मोदी ने भारत के हितों और 1972 के शिमला समझौते को धोखा दिया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, एक कमजोर विदेश मंत्रालय का खंडन ही काफी नहीं है। पीएम को राष्ट्र को बताना चाहिए कि ट्रंप और उनके बीच बैठक में क्या हुआ था। इसी प्रकार ट्रंप के बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा हो गया जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज किया। विदेश मंत्री ने कहा कि शिमला समझौते और लाहौर संधि के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देश ही मिलकर इसे सुलझाएंगे।

भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वन सेवा (2018-20 बैच) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें हमारे देश की वन संपदा की रक्षा और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। हालांकि, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना, संरक्षण की निरंतरता और सफलता सामूहिक जागरूकता पर निर्भर है। हमारे देश के जंगलों और उसके आसपास आदिवासियों सहित बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। जंगलों के माध्यम से ही वे भोजन और चारे की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग सरल और परिश्रमी होने के साथ-साथ बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। वे अपनी परंपराओं और मान्यताओं के तहत जंगलों का सम्मान करते हैं। वनों की रक्षा के लिए कोई भी उपाय इन लोगों की बुनियादी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें भागीदार के रूप में शामिल करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संयुक्त वन प्रबंधन मॉडल ने वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों और समुदायों के साथ काम करने की परिकल्पना की है। स्थानीय लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयासों के साथ आजीविका के अवसरों को जोड़ना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक बार जब लोग और समुदाय वन प्रबंधन के प्रयासों में शामिल हो जाते हैं तो वन अधिकारी जैसा समाधान चाहते हैं, वह अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो जाएगा।

रावत के बाद नरवाने होंगे अगले सेनाध्यक्ष

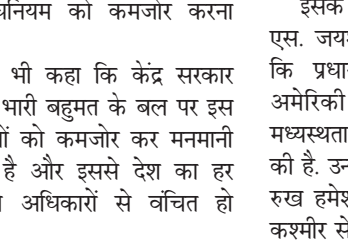

नईदिल्ली (आरएनएस)। सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सेना का अगला उपप्रमुख नियुक्त किया गया है. लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू का स्थान लेंगे जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने अगेल सेना प्रमुख पद बन सकते हैं. दरअसल वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 31 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने 37 वर्ष की अपनी सेवा के दौरान कई पदों पर कार्य कर चुके हैं और आतंकवाद निरोधक माहौल में काफी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन और पूर्वी मोर्चे पर एक इंफेंट्री ब्रिगेड की भी कमान संभाली है. इसके अलावा सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के लिए नये जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे.

सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल ए एस क्लेर को दक्षिण-पश्चिम कमान का जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है और वो लेफ्टिनेंट जनरल सी माथेसन का स्थान लेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल माथेसन 31 अगस्त को रिटायर होंगे. लेफ्टिनेंट जनरल आई एस घुमान को मध्य कमान का जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है. वो लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण का स्थान लेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल आर पी सिंह को पश्चिमी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है. वो लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह का स्थान लेंगे जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

अब आम्रपाली के अधूरे फ्लैट्स बनाएगी एनबीसीसी

» सुप्रीम कोर्ट का फैसला

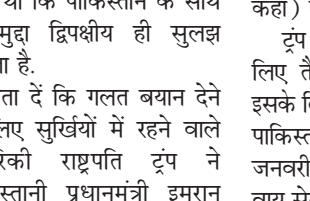

नईदिल्ली (आरएनएस)। आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एनबीसीसी को आम्रपाली के अधूरे फ्लैट के निर्माण करने को कहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के मालिक के खिलाफ ईडी को मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच करने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आम्रपाली के हजारों बायर्स की इस फैसले पर नजर थी. आम्रपाली के 40 हजार से ज्यादा फ्लैट बायर्स के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है. कई साल से ये बायर्स फ्लैट के लिए चक्कर लगा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया. फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को आदेश दिए हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट पूरे कर ग्राहकों को सौंपे जाएं. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि घर खरीदारों की रकम डायवर्ट करने के मामले में कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ जांच की जाए.

सूचना के अधिकार संशोधन विधेयक पर सोनिया ने की केंद्र की आलोचना

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने सूचना के अधिकार कानून में संसोधन को लेकर केंद्र सरकार पर लोगो के अधिकार छीनने का आरोप लगते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में मिले भारी बहुमत का दुरूपयोग कर रही है।

गांधी ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार संसद में 2005 में सर्वसम्मति से पारित सूचना के अधिकार कानून में केंद्रीय सूचना आयुक्त को दी गए शक्तियो को काम करना चाहती है। इस आयोग को सत्ता में पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरह स्वतन्त्र बनाया गया था।

उन्होंने कहा इस कानून को विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था। इस कानून का इस्तेमाल अब तक पांच लाख से अधिक देशवासी कर चुके हैं और हर स्तर पर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई संस्कृति को बल मिला है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है और समाज की कमजोर वर्गों को लाभ मिला है। गांधी ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर करना चाहती है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार संसद में मिले भारी बहुमत के बल पर इस तरह के कानूनों को कमजोर कर मनमानी करना चाहती है और इससे देश का हर नागरिक अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा।

पीएम ने नहीं किया आग्रह, भारत-पाक ही करेंगे समाधानःजयशंकर

» कश्मीर मध्यस्थता पर संसद में हंगामा

नईदिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर पर दिया गया बयान संसद के दोनों सदन में भी गूंजा. मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने ये मामला उठाया और केंद्र को घेरने की कोशिश की. कांग्रेस के आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब की मांग की.

इसके जवाब में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मध्यस्थता की कोई अपील नहीं की है. उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है कि कश्मीर से मुद्दे पर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और किसी तीसरे मुल्क की दखल नहीं हो सकता. पाकिस्तान के साथ बातचीत आतंकवाद के खात्मे के बाद ही मुमकिन है. दूसरी ओर लोकसभा में भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम के बयान की मांग की है.

राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दावा किया है वह बिल्कुल गलत है, पीएम मोदी ने इस तरह की कोई मांग नहीं की है. उन्होंने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ये दावा पूरी तरह से गलत है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा, भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो भी बातें होनी हैं वह सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा हैं. पाकिस्तान से किसी भी तरह के मसले पर तभी बात हो सकती है, जब वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा. मैं कहना चाहूंगा कि शिमला और लाहौर समझौते के तहत ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के साथ हर मुद्दा द्विपक्षीय ही सुलझ सकता है.

बता दें कि गलत बयान देने के लिए सुर्खियों में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मीडिया से बातचीत की. इस दौरान कश्मीर मसले पर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था. ट्रंप ने कहा, मैं दो हफ्ते पहले प्रधान मंत्री मोदी के साथ था और हमने इस विषय (कश्मीर) के बारे में बात की. और उन्होंने वास्तव में कहा, क्या आप मध्यस्थ या मध्यस्थ बनना चाहेंगे मैंने कहा, कहाँ (मोदी ने कहा) कश्मीर.

ट्रंप ने कहा कि वह मदद के लिए तैयार हैं, अगर दोनों देश इसके लिए कहें. बता दें कि भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जनवरी 2016 में पठानकोट में वायु सेना के ठिकाने पर हमले के बाद से पाकिस्तान से बातचीत बंद है.